[Shri Ratanlal Kishorilal Malviya.]

lowed by the Government so far is being followed in this amending Bill also. We know this much that the Government of Jammu and Kashmir have been adopting the enactments which have been passed by us, and when they feel that application of this measure is also necessary for the State of Jammu and Kashmir, I have no doubt that that Government will adopt it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MOTION *RE* REPORT OF THE HINDUSTAN HOUSING FACTORY LIMITED

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"१९६१-६२ के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान हाउसिंग फेक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के नवें वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो २३ जनवरी, १९६३ को राज्य सभा की मेज पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

उपसभापति महोदया, जहां तक मैं समझता हूं मकानों की समस्या केवल दिल्ली की या किसी एक गांव की समस्या नहीं है । यह सारे देश की और एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, जहां तक कि मकानों का सवाल है, यह भोजन और कपड़े के बाद तीसरी आवश्यकता है । इसी दृष्टि से यूनाइटेड नेशंस में भी जो इकोनामिक ऐंड सोशल कौंसिल है उसने खास तौर से एक हाउसिंग कमेटी बनाई इस समस्या की जांच करने के लिये कि किन-किन राष्ट्रों को क्या-क्या सहायता दी जानी चाहिये और किन-किन राष्ट्रों से क्या क्या सहायता ली जानी चाहिये । तो इन सारी बातों पर विचार करके उन्होंने भी एक कमेटी बनाई और जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने इसके लिये कर्ज भी देने का सुझाव दिया है और संभवत: इसके लिये कर्ज देने की भी व्यवस्था की जा रही है ।

जहां तक अपने देश का सवाल है, अपने यहां लगभग साढ़े बांच करोड़ मकान हैं और अगर एक-एक की जांच की जाये तो ऐसा लगता है कि कम से कम ७५ प्रतिशत ऐसे मकान मिलेंगे---मैं तो बड़ा लिबरल एस्टीमेट करता हूं---जो आदमियों के रहने के काबिल नहीं है । इसके बावजूद भी उनमें रहना पड़ता है क्योंकि उसके लिये मजबूरियां है । इस दिशा में हमारे यहां भी जो कार्य प्रारम्भ किया गया हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के अन्तर्गत, वह इस दिशा में एक सही कदम है कि हम भी इस सम्बन्ध में कुछ कर सकें ।

विदेशों में भी इस समस्या को हल करने के लिये फोम कंक्रीट, प्रीस्ट्रस्ड ऐंड प्रीकास्ट कंक्रीट का उपयोग प्रारम्भ किया गया और उसके अन्तर्गत उन्होंने भी कार्यक्रम शुरू किया । अपने यहां सब से पहले यह काम विभागीय स्तर पर गवर्नमेंट हाउसिंग फैक्टरी द्वारा किया जाता था, मगर वह ठीकठाक चला नहीं । फिर १९५३ में एक इंडो-स्वैडिश कम्पनी के साथ ज्वाइंट वेंचर 'joint venture' किया गया और इस कार्य को आगे चलाया गया । एक दो साल तक वह कम्पनी चली, मगर उसमें १९५३ से १९५५ तक १४·७ लाख का घाटा रहा । फिर उस ज्वाइंट वेंचर को खत्म करके गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में ले लिया । १६ अगस्त, १९५५ को उसे पूर्णत: शासन ने ले लिया और १६ अक्तूबर, १९५५ को हमारी सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी उसके लिये बैठाई कि वह जांच करे कि हाउसिंग फैक्टरी को रखें या डिसपोज़ आफ कर दें और अगर रखें तो लाभ में कैसे

उसको चलाया जा सकता है । उस कमेटी ने इन सारी बातों की जांच की और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी । उसने कहा कि जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम काम नहीं कर पा रहे हैं । दूसरे हमारे माल को बेचने की व्यवस्था ठीक नहीं है और माल को बेचने की व्यवस्था ठीक नहीं होने से हम उत्पादन भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं । इसलिये बिक्री की व्यवस्था ठीक की जाय । नई मशीनों का भी उन्होंने सुझाव दिया । उन्होंने यह भी बताया कि हमारी कैपेसिटी को बढ़ाया जाना चाहिये और नये आइटम्स लिये जाने चाहियें और जो वेस्ट होता है उसको भी उपयोग में लिया जाना चाहिये ।

हमारी फैक्टरी का जहां तक सवाल है, वैसे तो अभी हमने मकानों का प्रीफैब्रिकेशन प्रारम्भ किया ही है, मगर इसके साथ-साथ खास तौर से तीन हिस्सों में हमने इस काम को बांट रखा है, जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है । पहला फोम कांक्रीट है जिसके द्वारा इंसुलेशम ब्लाक तथा पार्टिशन ब्लाक तैयार किये जाते हैं जो मुख्यतः वातानुकूलित भवनों के निर्माण में और दूसरे कामों में लाये जाते हैं । दूसरा प्रीस्ट्रस्ड और प्रीकास्ट कांक्रीट डिपार्टमेंट है जहां पर बिजली के high transmission poles, street light poles, fencing posts, light and heavy industrial beams, precast roofing elements, vibrated cement concrete pipes, R.C.C. रेलिंग, लीफ्दान वग़ैरह बनाने का काम होता है । तीसरा डिपार्टमेंट है वुड वर्क का जहां लकड़ी के दरवाज़े, खिड़कियां वग़ैरह तैयार की जाती हैं जिस से मकान बनाने की सारी सामग्री तैयार हो सके । जैसाकि हमारी रिपोर्ट में है, कई मकान हम ने बड़ी जल्दी, कम स्पेस में और बहुत अच्छे तैयार किये और इस दिशा में हम ने कुछ किया है । इनमें से जहां तक दो विभागों का सवाल है फोम कांक्रीट और प्रीस्ट्रेस्ड और प्रीकास्ट कांक्रीट विभागों का, उन का मुख्यतया सम्बन्ध सीमेंट और लोहे से होने की वजह से हमारी सरकार इस मामले में तो प्रगतिशील रही और लाभ में भी चली । हमारी जो रिपोर्ट है उस में यह देखने में आया कि हमारा वुड वर्क डिपार्टमेंट दिवालिया का हिसाब देता रहा, घाटे का हिसाब देता रहा और उसको हमारे विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सिक मैन 'sickman' की उपाधि दी और यह बताया कि जितना लाभ हम कमा कर के लाते थे वह वुड डिपार्टमेंट खा जाता था । अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी जाय तो उन्होंने यह सुझाव दिया था कि हमारे वुड वर्क डिपार्टमेंट की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हमें काम करना चाहिये उसे बढ़ाना भी चाहिए । उस समय २० लाख रुपये के माल की क्षमता थी । उन्हों ने कहा कि उस की जगह २५ लाख रुपये की क्षमता बढ़ानी चाहिये । उन्होंने सीज़निंग प्लान्ट और ऐसे ही दो तीन प्लान्ट का सुझाव दिया था कि उन को लेना चाहिये और जो लकड़ी वेस्ट होती है उस का उपयोग करना चाहिये । मगर इस डिपार्टमेंट में कुछ उल्टा काम हुआ और उल्टा काम ऐसा हुआ कि सन्, १९५६-५७ में १५.६४ लाख का माल तैयार हुआ । उस की जगह सन् १९६१-६२ में ४ ४१ लाख का माल रह गया । इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ठीक तरह से अमल में नहीं आ सकी या एक्सपर्ट कमेटी ने ग़लत राय दी यह मैं ठीक कांक्लुज़न ड्रा नहीं कर सका ।

इतना ही नही सन् १९५९-६० में वुड वर्क डिपार्टमेंट में एक नया काम हाथ में लेने के लिए सुझाव दिया गया था जिस से यह डिपार्टमेंट लाभ में रहे । वह काम यह था कि जो पेंसिल की लकड़ी होती है वह बनाई जाय । वह लकड़ी विदेशों से काफी मंगानी पड़ती है और उस पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है । ऐसा करने से उस की भी बचत होगी और यह डिपार्टमेंट भी लाभ में रहेगा । १९५८-

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

५६ में यह योजना बनाई गई, १९५९-६० में उस पर एक्सपेरिमेंट किये गये और १९६०-६१ में उसका क्या हुआ, भगवान जाने क्योंकि इस रिपोर्ट में उसका कोई उल्लेख नहीं है, उसकी चर्चा तक नहीं की गई है। यह कहा गया है कि इस डिपार्टमेंट का काम अब धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। वैसे तो हमारी एक्सपर्ट कमेटीने और भी सुझाव दिये थे कि नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन से सम्बन्ध रखा जाय और उसकी जो आवश्यकताएं हों उनको पूरा किया जाये, और स्टेंडर्ड दरवाजे और खिड़कियां वगैरह सब बनाई जायें मगर इन सबके बावजूद यह देखा गया कि इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में हमारे विभाग ने प्रयास किया होगा, मगर हमारी सरकार का यह जो डिपार्टमेंट है, इस मामले में वह बिलकुल असफल रहा और इन तीनों डिपार्टमेंट्स को देखा जाय तो इसके केवल दो ही सेक्शन लाभ में रहे और एक सेक्शन घाटे में रहा। उसके सम्बन्ध में मैं ने सोचा तो ऐसा लगता है कि शासन की लोहा एवं सीमेंट के बारे में विशेष परिस्थिति होने की वजह से हमारे इस वुड डिपार्टमेंट को छोड़ कर के बाकी और डिपार्टमेंट लाभ में चलते हैं और बाकी लकड़ी का विभाग घाटे में चलता है। सीमेंट और लोहा फोम कांक्रीट प्रिकास्ट और प्रिस्ट्रेस्ड कांक्रीट के लिये आवश्यक है और यह आपको नियंत्रित दर पर आसानी से मिलता है। मंत्री महोदय ने हमें बड़ा लाभ बता दिया है और पहले ही मौके पर डिविडेंड डिक्लेयर करने का उन्होने सोचा था लेकिन वह "आसमान से पटका, खजूर में अटका" वैसे ही खजूर में अटक गया, परन्तु अगर देखा जायेगा तो पता चलेगा कि लाभ केवल सरकार के कुछ करने कारण नही हुआ है बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकार की एक विशेष स्थिति है जिसके द्वारा उसे लोहा और सीमेंट नियंत्रित दरों पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और दूसरे यह कि शासकीय विभाग इनको खरीदते हैं, शासकीय या अर्ध-शासकीय विभाग जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह ही इनके खरीदार हैं, इनको ही इन के माल की बड़ी आवश्यकता है। तो जो माल इसमें लगता है वह आसानी से मिलता है और सस्ता भी पड़ता है और यह भी है कि दूसरे जो लोग हैं, कम्पीटीशन में, वे इतना अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं कि हमारी सरकार के और उनके मुनाफे को देखा जाय तो उसमें काफी अन्तर है और फिर उनको लोहा और सीमेंट कम मिलता है इसलिये सरकार के साथ कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकते हैं। वैसे तो मंत्री महोदय कहेंगे कि जितना कैपिटल है, जो रिजर्व है और जो लोन वगैरह है उन सब को जोड़ा जाय तो १२ परसेंट का लाभ है मेरा निवेदन है कि आप ने जो इतना लाभ बता दिया है वह आप ने स्वयं कुछ कर के किया ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वह इस वजह से है कि आपकी विशेष परिस्थिति है जिसमें कि आप अच्छी साइट ढूंढ सकते हैं और आप को सारी सामग्री वगैरह आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो उस की वजह से लाभ हुआ। अगर आपको क्षमता दिखानी है तो वुड वर्क डिपार्टमेंट---लकड़ी के विभाग में दिखानी चाहिये जिसमें कि नियंत्रित सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। आप लड़का के दरवाजे और लकड़ी की खिड़कियां बना कर बेचते और मार्केट में ठहर नहीं पाते अगर उसमें कुछ लाभ बता पाते तो मैं समझता कि आप सक्षम थे। आपको जो विशेष परिस्थिति है उसके अन्तर्गत आप लाभ बताते हैं तो यह कोई क्षमता का द्योतक है ऐसा मैं नहीं मानता। तो हिसाब भी किया गया और लाभ भी बताया गया और रिजर्व वगैरह में काटपीट कर के ३ परसैंट का डिविडेंड देने का सोचा मगर उसके लिये राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अभी यह डिविडेंड लेने की जरुरत नहीं है, पड़ा रहने दो फिर विचार करेंगे, चूंकि गवर्नमेंट की फक्टरी थी, एक जेब से ले कर दूसरे जेब में

देना था इसलिये ऐसा किया लेकिन जहां तक हिसाब-किताब का बात है वह पूरा नियमानुसार होना चाहिये । आप लोन लेते या हमारा इसका जो अथोराइज्ड कपिटल है उसको बढ़ा कर के कुछ करता, जो ४० लाख वगैरह रखा है उसको पूरा का पूरा कर सकते थे और उसके लिये कोई इंकार नहीं करता मगर जहां तक हिसाब-किताब का सवाल है ३ परसेंट का डिविडेड मिलना चाहिये था । जब इतना रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ता है तब उसका कोई डिविडेंड नही लेते यह कोई न्यायसगत प्रतीत नहीं होता है । तो आपको इस दिशा में कुछ करना पड़ेगा ।

अब रिपोर्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें स्थिति का सहा चित्रण नहीं है । रिपोर्ट को देख करके बैलेंस शीट या प्राफिट एंड लास का एक्जक्ट पिक्चर मालूम कर लें वैसा कुछ नही है । इस रिपोर्ट में कजदारों का हिसाब बिल्कुल सही नहीं है । दूसरे यह कि किताबों में माल कुछ है और वास्तविकता मे कुछ है, जो बुक्स में दिखाया गया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाय तो कुछ और ही मिलेगा । स्टोर्स में फर्क है, स्टाक्स में फक है । फिर वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में एडहाक एलाउंस १० परसेंट का दिया है । फिर स्टाक में जो सामग्री होना था उसका भी वैल्युएशन मार्केट रेट पर होना चाहिये लेकिन एडहाक बेसिस पर २५ परसेंट कम करके रख दिया है । तो ऐसी स्थिति में अगर यह कहा जाये कि हमारा यह सारा चित्र बिल्कुल सही है और हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है तो मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं बल्कि उल्टा यह आरोप लगाता हूं कि यह आंकड़ों का जगलरी है । जैसे कि जादूगर अपने भ्रमजाल में डालने का प्रयत्न करता है वैसे ही आप भी आंकड़ों का जगलरी करके भ्रमजाल में डालने का प्रयत्न करते हैं । आप वैसा पिक्चर नहीं देना चाहते हैं जो कि बिल्कुल सही है । इस रिपोर्ट को, इन आंकड़ों को देखने से लगता है कि हम वास्तविकता से, सत्य से बहुत परे हैं ।

रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कई बात प्रकाश में आती है । ४० लाख की पूंजी में से जो रकम कर्जदारों से जो लेना है उसमें से ५,९९,२८१ रु० ऐसा है जो कि डाउटफुल है, डेट्स डाउटफुल है और अभी तक कंफर्म भी नहीं कर पाये हैं, चाहे वह डिपार्टमेंट्स हों या दूसरे हों, ये डाउटफुल डेट्स के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं । दूसरी बात यह है कि किताबों के आधार पर माल की जांच की गई तो उसमें क्या हुआ, उसमें ७८, ३८३ रु० १२ नये पैसे का वृद्धि हो गई और जो जांच का तो घटती आई ४८, ४५४ रु० २८ नये पैसे की सामग्री थी । तो इस तरह से हिसाब-किताब है । इसमें भी कुछ गड़बड़ लगता है । स्टाक्स को स्थिति देखी गई तो १,७३,४९० रु० ३० नये पैसे का फिनिश्ड माल था और ७८,४३९ रु० २२ नये पैसे का रा मैटीरियल था और ये दोनों कुल २,५२,९२९ रु० ५२ नये पैसे का माल हुआ । दो साल हो चके है और इसके बाद भी इसको उपयोग मे नहीं लाया जा सका है और न यह विक्रय किया जा सका है । तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ डिसाशन ले कर के करना चाहिये, नहीं तो आगे जा कर यदि इसकी बिक्री नही होगी और इसका उपयोग नहीं होगा तो फिर यह पुराना माल हो जायगा और इसलिये इसका ५० परसेंट वैल्यूएशन कर के और प्राफिट एड लास में डेबिट कर के दिखा देंगे और जो अभी १२ परसेंट का प्राफिट बता दिया है वह कल कम हो जायगा । इसलिये इस दिशा में भी कुछ किया जाना चाहिये ।

अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूंगा एक तो यह है कि हमारी जो रिपोर्ट है उसमें सही चित्र दिया जाना चाहिये, जितने भी डाउटफुल डेट्स हैं जिनका कंफर्मेशन नीचे पाया है उसके बारे में रिपोर्ट को पढ़ कर ऐसा लगता है कि आडिटर्स ने अपनी रिसपांसिबिलिटी बिल्कुल छोड़ दी है और सरकार पर ही सारा का सारा डाल दी है, सरकार यह चाहती है कि ऐसा पोल चलता रहे तो ठीक है । यह लिखा है :

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

"In the absence of confirmations of the outstanding balances under Sundry Debtors due from the different Government Departments, the auditors are unable to express any opinion as to their realisability."

वसूली की क्या स्थिति है इसके बारे में आडिटर्स कुछ कहना नहीं चाहते फिर भी तमाम बैलंस शीट को आडिट करके भेज ही देते हैं। तो यह जो गड़बड़ की स्थिति है उसको भी हमारी सरकार को ठीक करना चाहिये।

दूसरे, आवास की समस्या की गहराई की अनुभूति करके तीव्र गति से कार्य होना चाहिये। इस समस्या से मंत्री महोदय को तकलीफ मिलती ही होगी क्योंकि इसके लिये सभी उनके पास आते हैं, सरकारी कर्मचारी भी आते हैं। तो इस समस्या की अनुभूति की जाय। सभी कहते हैं कि हमारे लिये मकानों की व्यवस्था कीजिये। तो समस्या की अनुभूति कर के शासकीय तथा अशासकीय दोनों क्षेत्रों में प्रगति की जाय और दोनों का विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दोनों क्षेत्रों को मिल कर इस काम को करना है। ऐसा नहीं हो कि अपने में ही कंसेंट्रेट कर के रखें और दूसरे क्षेत्र में, अशासकीय क्षेत्र में इसको नहीं चलने दें। यह ठीक नहीं होगा। दोनों ही क्षेत्रों में यह कार्य चलता है जिससे कि आवास समस्या हल हो सके।

तीसरी बात यह है कि युनाइटेड नेशंस द्वारा जो इसके बारे में एक कमेटी बनी है उससे जो भी लाभ मिल सकता है वह लेना चाहिये। इंटरनेशनल फाइनेंस से रुपया वगैरह लेने का भी हमें प्रयास करना चाहिये।

चौथी बात यह है कि जिन देशों ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है, जैसे कि रूस, पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया, वगैरह और खास तौर पर रूस में इसके बारे में विशेष रूप से परीक्षण हुए है तो उन देशों के ज्ञान का भी लाभ लेना चाहिये। हमारे यहां से इंजीनियर्स भेज करके वहां के ज्ञान का लाभ लिया जा सकता है तो उसे लेने का प्रयत्न करना चाहिये और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य कर सकें ऐसा प्रयास करना चाहिये।

पांचवी बात यह है कि हमारा देश भारतवर्ष ऐसा है कि कहीं इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि कुछ कहना नही और कहीं गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि कुछ पूछिये नहीं और कहीं बहुत ज्यादा बरसात होती है तो कहीं बरसात का पता नही ही, हमारे यहां भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु है। ऐसी स्थिति है दिल्ली में बैठ कर एक तरह का माडल तय कर दें कि इस तरह का हाउसिंग होना चाहिये तो उससे हम सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिये अलग अलग जलवायु के क्षेत्र में हमें एक्सपेरिमेंटल हाउसिंग करना चाहिये और एक्सपेरिमेंटल हाउसिंग करना चाहिए और एक्सपेरिमेंटल हाउसिंग करके उनका डिमांस्ट्रेशन करना चाहिये और डिमांस्ट्रेशन के बाद अगर लोगों के उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हों तो उन पर भी विचार किया जाना चाहिये और इस तरह से सस्ते-सस्ते मकान अलग अलग जलवायु के अनुसार बनाना चाहिये। तो इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि हमारी आवास की जो समस्या है वह हल हो सके।

मेरा छटा सुझाव यह है कि फोम कांकीट प्रिस्ट्रेस्ड, प्रिकास्ट कांक्रीट जो है उसमें मुख्यतः लोहे और सीमेंट को उपयोग में लाते हैं और लोहे तथा सीमेंट की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे साधारण नागरिकों को इनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। हमारे मंत्री जी के डिपार्टमेंट को भी इनकी कमी महसूस होती होगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस फैक्टरी द्वारा नये नये एक्सपेरिमेंट्स करके और दूसरे नये नये सबस्टीट्यूट्स ढूंढने चाहियें जैसे कि पत्थर का भी उपयोग किया जा सकता है, चूने का भी उपयोग किया जा सकता है। और कहीं कहीं घास फूस बांस आदि को भी काम में

लाया जा सकता है। तो इन सारे पर एक्सपेरिमेंट्स कर के सबस्टीट्युट्स निकालना चाहिये। इस बारे में विचार करके कार्यवाही की जायगी तो ज्यादा अच्छा होगा।

आखीरी सुझाव मेरा यह है कि आज तक हमारा जो दृष्टिकोण रहा है वह विशेषतः शहरों के लिये केन्द्रित रहा है। यह बात सही है कि शहरों में रहने की समस्या बहुत कठिन है, यहां यह बहुत बड़ा प्राब्लम है कि अच्छा सैनिटरी हाउस हो मगर इसके साथ ही साथ हमें अपना थोड़ा सा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लगाना है। मगर हम अपना कार्यक्षेत्र थोड़ा बढ़ा कर ग्रामीण क्षेत्र में भी ले जायेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस दिशा में भी हमें कुछ करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहने के लिये उतनी ही कठिनाई है, वैसे वहां साफ हवा ज़रूर मिलती है मगर बरसात के दिनों में उनकी हालत बहुत खराब रहती है, न मालूम कितनी बार उनके मकान में पानी टपकता तथा जगह गीली होती है और उनको इधर उधर रहना पड़ता है। उसी मकान में जानवर भी रहते हैं और आदमी भी रहते हैं, जानवरों का रिफ्यूज़ वगैरह वहीं सड़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि इस हाउसिंग फैक्टरी के माध्यम से हम इस दिशा में भी विचार करें और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के बारे में भी हम कुछ करें ताकि उनको सस्ते मकान मिल सकें। हमें यह देखना है कि उन्हें भी वैसे ही सीमेंट के और कास्ट-सीमेंट के बढ़िया मकान जो हैं वह दे सकते हैं या नहीं। अच्छे मकानों के चित्र तो इतने अच्छे दिए गए हैं कि कुछ पूछिए नहीं, मगर उन चित्रों का एक हिस्सा भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बन सके तो ज्यादा अच्छा होगा।

इन सुझावों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इन सुझावों को ध्यान में रख कर आगे की रिपोर्ट ज़रा ज्यादा एग्जेक्ट बनाने की कृपा करेंगे और हमारे देश में जो आवास की समस्या बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है उसको हल करने के लिये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम करेंगे और जो वुडवर्क का काम आपका ठंडा पड़ता जा रहा है उसको भी ठीक करने की कृपा करेंगे। यही मेरा निवदन है।

The question was proposed.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, this is a very interesting report, the consideration of which has been moved with a more interesting speech. The learned Mover is not prepared to give the Government credit any achievement.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : आपकी समझ का फेर है।

श्री अर्जुन अरोड़ा : यह आपकी निजी समझ की फेर का सारा नमूना था जो आपकी स्पीच थी।

The Company is a public sector company and therefore, according to the learned Mover, if it makes profit, it is because of the peculiar situation of the Government. If there is a particular department which, for some reason unknown to the learned Mover, does not make profit, that is the acid test of the efficiency of the Government.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सही बात कहने का तो हमें भी अधिकार है।

श्री अर्जुन अरोड़ा : आपको खूब अधिकार है, खूब बोलिए और उसके बाद जवाब देने का भी आपको मौका मिलेगा क्योंकि आप मूवर हैं लेकिन थोड़ा सा सब्र करके दूसरों को भी सुनें। तभी आप देश का और समाज का भला कर सकेंगे।

So, if there is any department which for some reason unknown to the learned Mover does not make profit, that is the acid test of a public sector undertaking. I have listened to the debate

[Shri Arjun Arora.]

and a number of debates on public sector undertakings in this House and the other and in the country at large. The usual accusation against the public sector is that it does not start making profit from the day the factory comes into being. Here is a factory which the Government took over because it was not being run by others properly. It was in 1955 that the Government took it over. The previous management was not running it satisfactorily. That is why the Government intervened and anybody who has even an inkling of working of industrial undertakings in this country and others know that once a factory is mismanaged, its production is not properly organised, it takes years, it takes decades to set things right. That is the complicated nature of industry today and I should have thought that the hon. Mover and other Members of this House will congratulate the Department concerned, the Ministry concerned, for salvaging this factory and making it profitable. With some knowledge of industries in this country, I can say that 12 per cent. return is a very good return. As a matter of fact the Labour Appellate Tribunal of India thought 6 per cent. return on capital as a very reasonable return. Even in the matter of Super Profits-Tax the Government of India has permitted 6 per cent. return. Six per cent. is considered in the country as a very reasonable return. This public sector undertaking makes just the double of that and I take this opportunity to congratulate the management for 12 per cent. return. That should not be a cause for anger and annoyance and for jumping up. It should be a matter of pride. The fact that the President of India has withheld dividend and the dividend has not been distributed, should not cause any embarrassment to anybody. If I have my way, with the rapid industrialisation of the country in view, with the need of expanding industries in view, I should say that for 10 or 20 years no dividend should be distributed. As a matter of fact what has happened in the country is that those in the private sector who make some investment get a tax holiday and they get a development rebate and they get fat dividends. So the private sector in the country had taken back all the capital from the industries by way of these tax concessions and fat dividends. Then it goes to the banks run by itself for working capital and the banks pay dividends. If the public sector concern, according to the Government decision, has not distributed its profits as dividend, where has the money gone? The money has not gone into the pockets of anybody. It is there, it is shown in the books. It is being used as the working capital of the company which means that the company does not have to go to the banks or to the Government for further finances. That is a very sound thing and I take this opportunity to congratulate the Minister who is responsible for this decision. There is no आंकड़ों की जगलरी jugglery as the hon. Member called it in this report. It is a very simple report. If there was any juggler entrusted with the preparation of this report, it would have been very easy for him not to give the departmental break-up of the working results. The report on page 5 gives the working results of each Department. Even a school lad conversant with company accounting knows the trick that in order to conceal a non-profit-making department the working results of various departments are lumped together and presented as one. In this case a great deal of intellectual and accounting honesty has been practised and the working results have been given department-wise with the result that the Member of the Jan Sangh Party has got hold of the wood-work department to pinpoint the inefficiency of the Government whose efficiency in the matter of prestressed concrete and foam-concrete he does not recognise. He says that the profits in these departments are due to the fact that the steel and cement are available to them at controlled prices. Now I would like the hon. Mover, in his reply, not

just now, to point out the factories which buy cement and concrete from the black market at prices higher than the controlled prices. As a matter of fact all factories of this nature which are engaged in the matter of prestressed concrete or which in any manner utilise cement and steel get their quotas. They engage their Liaison Officers to stay in Delhi and get quotas at controlled rates and my charge is that the private sector industry gets more cement and more steel at controlled prices than they need and there have been cases—and a number of convictions also—in which the private sector industrial undertakings get steel and cement at controlled rates according to quotas, get more material than they need and indulge in black market. So getting cement and steel at controlled rates is not a privilege of this particular factory. As a matter of fact, the chances are that this factory, being a public sector factory did not mis-utilise the cement and steel given to it at controlled rates.

The auditors have pointed out that the valuation of stocks has been shown below cost price. Well, apart from the correctness or otherwise of the accounting practice involved, I should say that as guardians of public funds we should feel proud about it, because if the current stocks of the factory were not shown at below cost price, the profits would have been higher, not 12 per cent but may be 18 per cent or 20 per cent. So this again shows that the Board of Directors are very conservative and they are honest and it has set a model of accounting practice which I should expect the hon. Mover of the motion would recommend to the private sector also.

There is, of course, mention of certain excesses and shortages in these stocks and the Report promises an enquiry. It says that the matter is being enquired into. This was in March, 1962 and I hope during the thirteen months that have elapsed the matter has been enquired into and I expect the Minister to make an announcement of the results of that enquiry.

Next, Madam, I must refer to the labour relations in this factory. It is a matter of great satisfaction that this factory has a canteen which runs on a no-profit and no-loss basis. And it is a very good thing that it provides meals at cheap rates and they charge only 13 naye paise for a full meal. That is something very satisfactory from the labour point of view. What happens is that in most of our factories they do not run any canteen and even when the law forces them or when the Factories Act compels them to run a canteen, they just provide black tea and some snack only. That, I must say, is a practice which defeats the very purpose of the provision in the Factories Act which made it compulsory for the factories to run a proper canteen for the workers. All factories and canteens should follow the good example of this factory and give mid-day meals to the workers at cheap rates. A full meal at 13 nP. I should say, is reasonable. It is also a matter of satisfaction, Madam, that this public sector undertaking is cooperating with the Labour Ministry in the workers' education scheme. I have noted with pain that a number of public sector undertakings do not cooperate with the Government in this scheme. I should expect the Minister of Industries who is by chance here now, to see to it that all public sector undertakings cooperate in the workers' education scheme of the Government of India's own Workers' Education Board.

It is, of course, a subject that causes some pain that differences between labour and management in this factory came to a head in 1961 and the dispute was referred to adjudication. When the Chinese attacked this country there was an industrial truce at the instance of the Government of India on 3rd November and one of the clauses of that industrial truce was that in order to ensure the smooth running of factories, matters pending in adjudication will be settled by nego-

[Shri Arjun Arora.]

tiations and when negotiations failed, they would be referred for arbitration and settled quickly. I do not know if that 1961 dispute which was referred to the Industrial Tribunal for adjudication is still pending. If it is still pending, it will be excellent if this Government undertaking settles the dispute and ensures smoother production and better labour relations during this period of emergency.

With these words, Madam, I congratulate the management of this factory.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam Deputy Chairman, we have heard two speeches, one was indirectly criticising this public sector undertaking and Mr. Chordia chose to go into accounts and certain other trivialities in order to press his point home. The other speech from that side confined itself to encomiums only. I think this company, or this Government undertaking, would certainly merit some measure of appreciation for its activities and I would not grudge this being given to it. But to me it looks a small affair, a small concern with an authorised capital of Rs. 75 lakhs which is almost the annual pocket allowance, shall we say, of the youngest son of Shri Shanti Prasad Jain? Therefore, it is not a very big concern that we are discussing in this Parliament and for two hours we will be discussing it. I wish it were a bigger affair, because in my view, this kind of housing factory or enterprise has an important part to play in solving the problem of modern housing and in conditions such as ours. Yet we find that for the last five or six years it has remained a very petty affair so to speak,, as an industrial undertaking.

I would ask Mr. Khanna who has done excellent service to the country by publishing the expenditure incurred by the Ministers on their electricity and water consumption and so on, to apply some of his constructive and creative mind to this particular field in order to explore the possibilities of expansion of the work of this factory. As I said, prefab housing has an important part to play in solving the problem of industrial, urban housing and if I may say so, to some extent, even rural housing. As we all know, in many countries now-a-days, especially in the Soviet Union and in other socialist countries where very great importance is attached to the solving of the problem of housing, these prefabricating housing factories have a special place and they are given particular care. Those who have been to Moscow will agree when I say that everyday you see new houses, flats and mansions come up there and new townships are coming up there all over the land. It would not be possible to achieve this objective in the conventional ways. They take recourse to prefabricated housing. On the basis of the annual calculation this housing comes to about 350 flats a day. All over the Soviet Union this prefabricated housing has made such rapid expansion of housing in industrial towns and cities and even in rural areas. In our country we do not envisage a situation when it will be possible to even touch the fringe of the problem if we go in the old way through conventional methods. I think therefore we have to go on a much bigger scale, not only here in one factory but we should start many other factories all over the country for prefabricated housing. Only then will we be in a position to tackle the problem of industrial housing, to begin with, and also to meet the requirements of the Government and other employees, low paid employees. When I speak of employees, I have them in mind. Possibly we can then expand in the villages also. But let us start with these towns, cities and so on.

Now, we have been discussing this question of slum clearance for some time and our Prime Minister gets very indignant when he looks at slums. When he goes to Kanpur and looks at slums he gets indignant. When he goes to Calcutta he feels the

same way but nothing really is done; even here in Delhi right under our nose we have got many people living in appalling conditions in the slums and nothing is being done, despite the fact that the Ministers with all their electricity and water live in the city of Delhi, about solving this particular problem of slum clearance in this capital city of ours. If you have to tackle this problem quickly and effectively, you cannot do so otherwise than by using this prefabricated methods. Therefore what we need today is not this small concern; we need to expand this. I would not be bothered about how much profit it is making. Even if it does not make any substantial profit, the investment will be more than compensated by the social welfare that it will have promoted. That is how I shall view this matter from the social welfare angle, not as a profit-making institution. If it makes profit, as indeed it has been making now, it is all to the good but suppose it does not make much profit to begin with, then we need not complain about it very much because we know it will have served the cause of the nation. Therefore, Madam Deputy Chairman, my contention is that there should be expansion. We do not want this small thing.

Mr. Chordia made a complaint about the dividend not being distributed. Well, that has been carried forward as has been pointed out by the previous speaker and it is going in investment and I think it is a very right course to take. After all, this distribution will take place again and it is going to be in the hands of the Government. It will not go outside to the private sector and so on.

There is one thing in this connection I would like to mention before I pass on to other aspects of the matter. Among the bankers it seems that in addition to the State Bank of India the Punjab National Bank Ltd. is also there. Why must we have a private sector bank? I do not think that the State Bank is incapable of holding the fortune of the Hindustan Housing Factory. I think it is quite capable of taking care of the savings or the liquid cash or whatever it is of the Housing Factory. I do not see any reason as to why the funds should be diverted to the privately owned bank and that too by a person who is well known in the country and whose activities have formed the subject matter of the Vivian Bose Enquiry Commission. I do not think that it was necessary to bring in the Punjab National Bank here. I say this thing as a matter of principle. On the contrary we should take over this Bank. And suppose we do not take over the banks. I do not think the Government funds or the funds of the semi-Government institutions such as these—these are Government institutions really—should be invested in private banks. They should remain with the State Bank of India and I would request the hon. Minister to look into this matter. I do not think he was personally responsible for it. He has inherited this institution and along with it the Punjab National Bank also as its bankers. I think he might consider the question of leaving the Punjab National Bank alone as far as this aspect goes.

Now I think the emphasis should be on prefabrication with a view to building tenements for the workers and flats for the low paid Government and other employees. I find that certain illustrations are here of certain things that are being built. It is good to look at anyhow, but we would very much like to see in the coming Reports the pictures of workers' tenements built with the help of these prefabricated materials. Similarly we would like to see big mansions being built containing a number of flats for accommodating middle class and lower middle class employees, whether they are Government employees or employees engaged in commercial or other private lines. That is how I would like the company to proceed.

But then I am not blaming this Company or the Minister. It depends upon the policy of the Government. If

[Shri Bhupesh Gupta.]

Government do not have a proper housing policy to tackle the problem of slums effectively and to meet the requirements of housing for the middle class and lower middle class employees it will naturally not be possible for the Minister to expand this. Therefore they are related matters. One depends upon the other. Here of course I would stress the need for having a proper housing project for Delhi to begin with and other towns around Delhi and for other places also. I think the Government is now thinking along old lines in this matter. What I would like the Government to do is to explore the possibilities of starting a number of such factories all over the country and utilise the material for quickly setting up prefabricated tenements and flats. I think here it would be necessary for the Government to draw upon the experience and knowledge of other countries which have done well in this particular field. Many delegations go to the Soviet Union. I understand that the Minister of Scientific Research and Cultural Affairs is going to the Soviet Union and I wish him good luck. But I think it would be profitable for this Government to send a proper team of men from this factory or from other similar concerns in order to study prefabricated housing in the Soviet Union, in Czechoslovakia, Rumania and other countries and draw upon their experience. It may also be necessary for them perhaps to invite certain experts here in order to get the technical know-how and to get out people trained in this particular line of industry.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): A good suggestion.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think we should draw upon the experience of those people. Our people are quite capable of doing so provided they are given the opportunity. Mr. Khanna is not very fond of foreign travel, I know. He need not go himself. I am not asking you to go there. You had better look after the water supply and electricity bills of Ministers. You have done a good job to the country. But send some officers to the Soviet Union and certain other countries, socialist countries of Eastern Europe. I have travelled fairly widely in that part of the world and I have seen what a great part this prefabricated housing has played. I went to a place there in 1957 and I saw particularly nothing there and when I went there two years later I found that a little township had come up there using this prefabricated material. I think we too can do such things given the right policy, given the resolve on the part of the Government to undertake housing on a big scale.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Madam, may I mention that when we were there—Mr. Sapru and myself—through the courtesy of Shri Bhupesh Gupta we saw these prefabricated buildings?

SHRI BHUPESH GUPTA: It was a great pleasure to accompany the two esteemed Members of this House just named when they saw the prefabricated houses and I think they will say the same thing as I am saying in regard to this matter. I think Mr. Khanna is a very enterprising person and in some ways he is a very courageous person. I think he should press for it. He got all the Ministers to reduce their water consumption, electricity consumption and all that. He did it. It is a good thing. Why cannot he show the same initiative and courage in the matter of expanding this particular project and of having a scheme which will give prefabricated houses for Government employees, workers and so on? I say, draw upon the experience of those countries which have produced wonderful results in this particular line. I would not like you to spend the resources at this stage for building certain non-essential constructions and so on. That, I think, can be left to others. I think emphasis should be on social welfare, emphasis should be on how quickly we can serve the needs of those people who are really suffering as a result of shortage in

housing or living in slums, and pre-fabricated housing projects, whether in this factory or otherwise, should be given a popular orientation. That is what I say. Here the Report says :—

> "The Delhi Administration have recently entrusted us the designing, planning and construction of pre-fabricated residential buildings or varying plinth area which are 24 in number. This is very encouraging."

I am a little surprised that he has got 24 projects from the great Delhi Administration and the Board of Directors find it encouraging. I should have thought that they should feel discouraged by it. Here in Delhi there is much greater scope for bigger assignments being given to this Housing Factory as against the 24 projects. I do not see any reason for any such encouragements. I should like to share encouragement with them in such matters, but here what has been given to them is very little. Why should it be 24 only? Why not 400 in number? This is what I would ask the Government. There is great scope for expansion and constructions along this line here. Therefore, it is a matter for the Delhi Administration as a policy. And I cannot blame Mr. Khanna or the Board of Directors here because if they do not get a policy backing and orders flowing from such a policy, they cannot do very much in the matter. That is why, as you will see, it remains a very small concern.

Then with regard to accounting and all that I do not wish to say much. Its business is also very limited. If you will see, here it is of the order of Rs. 75,42,109. It is very limited. They have got stock in hand and so on. Now, this again is not a very good performance. The capital investment is also not very much for that. It may be considered to be a sizeable business, but we are not satisfied, not because they are not willing to expand their business but because they are not in a position to do so on account of certain policies of the Government. Now, here I find that the General Manager gets Rs. 22,739. Well, I take it that it is his salary and allowances. Now, you have to consider whether it is not a big sum for a company of this kind. As I have said, its authorised capital is Rs. 75 lakhs, but actually the subscribed capital is Rs. 40 lakhs. For a concern of this kind, I think this salary would seem somewhat heavy. Well, if it is not considered heavy and the Government has sufficient justification for it, I do not mind it because many other people draw much more than this. But to me it would seem that he is rather very highly paid. I should be satisfied as a General Manager in such a concern, if I were one, with a salary of, say Rs. 1,200 or so. Not more than that. I should be satisfied with that. With expansion, you can increase the salary. I do not see why we should pay the same high salary as we pay in other concerns just because it is a public sector undertaking. On the contrary, the conditions of workers should be attended to and improvement should be made. The staff should be well looked after. What has been said here is good, but I have no practical knowledge or actual knowledge of the conditions under which the workers live. If they are looked after well; it is all to your credit, but it seems that there is an industrial dispute between the workers and the management and the matter is pending before the Tribunal. I take it that the matter is unresolved and I agree with Mr. Arjun Arora when he made the suggestion that there should be bilateral talks in order to bring about a settlement to the satisfaction of the workers, since it is a concern in the nature of a Government undertaking whose object is to serve the public without being bent on making profits as such. Now, I do not wish to say much because I would like this subject to be discussed. I would like such

[Shri Bhupesh Gupta.]

undertakings to be expanded. This is my whole contention. That is why I have risen to speak. The Government did a good thing by taking over the concern from the private sector. It is a good thing that they did in 1955. I only hope that this example would be followed. It belies the allegation that the Government is not in a position to run undertakings of this kind or industrial undertakings. Our experience is this. Whatever undertaking the Government has taken over from the private sector, which is responsible for malpractices and mismanagement, the Government has given a far better account of the administration of such concerns. For one thing, those matters are discussed in Parliament. If it were in the hands of the private sector, we would not have been in a position to discuss it at all. Only the shareholders would have some say and most of the shareholders would not attend the meeting. The matter would be settled by the family concerned or owners concerned, as happens in the country. Therefore, we say that the time has come to follow this example.

For example, under section 237 the Government has ordered an enquiry into five concerns of Dalmia-Jain, including Sahu-Jain. I do not see why these concerns should not be taken over. The management of these concerns should be taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, rather than left in the hands of those very people against whom serious allegations have been made. I say this because the private sector always makes accusations against the Government whenever it comes forward to take over certain private sector industries and to run them in the public sector. Here is an example of a well-run, on the whole well-run unit as far as the Report goes. If the Reports have told us not the truth half truth . . .

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION (SHRI MEHR CHAND KHANNA): The full truth.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Khanna says that he has told the truth. I am prepared to accept Mr. Khanna's assurance after the bills that he produced, after the material that he gave us about the consumption of certains things by his colleagues in the Ministries. I am prepared to accept it. Now, here is an example of good management, if the Report is true, of a concern by the Government or by State Officers and so on. I think this example should be known to the country. There are concrete refutations of the charges by the gentlemen of the private sector who day in and day out want to make out, despite all their limitless malpractices and corruption, that the public sector industries are not well run and that those who are at the helm of such industries are not men who are capable of business management and so on. Therefore, I would like these things to be known. But what I say, Madam Deputy Chairman, finally in this connection is that we need expansion of such undertakings and we would like to debate such matters with a far better report which will give us a much better and more encouraging picture of the development of our housing factories with a view to solving the most acute problem of housing that our people are facing today.

4. P.M.

This is all I wish to say, and I wish Mr. Khanna good luck and I hope he will take some steps with a view to expanding this particular concern and also develop the undertakings on similar lines in other parts of the country under the aegis of the Central Government so that the State Governments can follow the example.

شری عبدالغنی - (پنجاب) : میڈم ڈپٹی چیرمین - میں نے بڑے ھی دھیان سے آج کی ڈبیٹ کو سنا - اس وقت میرے سامنے پبلک سیکٹر

کہ ں زیادہ خطرناک ہے یہاں تک کہ ایمرجنسی کے موقعہ پر فریدوں نے عوام نے درمیانی طبقے نے سپاہیوں کے لئے کافی کچھ دیا اور وہ کلکتہ کے چور بازار میں بکتا رہا کسی پرائیویٹ آدمی نے نہیں بیچا کسی پرائیویٹ آدمی کے ہاتھوں میں نہیں تھا - اس لئے اس رپورٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری کسوٹی دوسری ہے کہ آیا میں بھی اس طرح چلوں جیسے عام ہندوستان کا ہندو بھائی جذباتی اور باقی رہنے والا کرتا ہے - کوئی آپوچھتا ہے کہئے بچے کا کیا حال ہے تو کہتا ہے دونی بھر آرام ہے - دونی چونی اور روپیہ سے بات کرتے ہیں ہندوستان کے لوگ اس لئے پہلے میرے بھائی چوڑیا جی انکڑوں میں پڑ گئے اس کے بعد مسٹر اروڑا نے بارہ پرسنٹ کہکر ہمارے منسٹر صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ ان کے اوپر بڑا کریڈیٹ جانا چاہئے - اگر میں بھی انکڑوں میں جاؤں تو مجھے بھی اپنے منسٹر کو مبارکباد دینے میں خوشی حاصل ہو سکتی ہے لیکن میں رپورٹ کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آیا وہ اس ہندوستان میں جس ہندوستان میں کروڑوں انسان ہیں جن کو ایک وقت پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا جس دیش میں کروڑوں ایسے ہیں جن کو سر چھپانے کے لئے ایک چھوٹی سے چھوٹی جھونپڑی میسر نہیں ہے کیا اس اور پرائیویٹ سیکٹر کی بحث نہیں ہے - عام طور پر دوست کہتے ہیں کہ تم نیشنلائزیشن کے لئے کیوں کہتے ہو - میرا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی سرکار جو ہے اس میں پرائم منسٹر کا دماغ اس طرح ورک کرتا ہے جس طرح مسٹر بھوپیش گپتا کا دماغ ورک کرتا ہے اور آدھی ہی پالیسی کبھی کسی سرکار کو کامیاب نہیں کرتی ہے اور اگر سرکار فیل ہوتی ہے تو دیش فیل ہوتا ہے - اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر کمیونزم کا ہی راستہ اختیار کرنا ہے تو پبلک سیکٹر کو جتنا چاہیں بڑھائیں لیکن آج قالینوں کا تانا کا سوال نہیں میں دیکھتا ہوں کہ بوگس فرموں کو پرمٹ روز نت نئے دئے جاتے ہیں لائسنس دئے جاتے ہیں ووٹے دئے جاتے ہیں ان کی فیکٹریاں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں لیکن قرضے دے دئے جاتے ہیں - خدا کرے یہ بند ہوں بوگس کمپنیز کے بارے میں پارلیمنٹ ادھر یا ادھر ایوان میں بحث ہو ورنہ یہ جو ارجن اروڑا بھائی کو شکایت ہے کہ جتنے پرائیویٹ کنسرن ہیں ان کو جتنا کنٹرول کا سامان چاہئے چاہے سیمنٹ ہو لوہا ہو وہ اپنی ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں اور فالتو بلیک میں چلا جاتا ہے - مسٹر اروڑا خوب جانتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کی جو کچھ بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ اس سے

[شری عبدالغنی]

کنسرن نے کوئی ایسا انقلاب کیا یا اس انقلاب کی طرف کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے ان بے چاروں کو آسانی پیدا ہوئی ہو ان کو سر چھپانے کے لئے جگہ مل سکی ہو - اگر ایسا میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس سے میں یہ محسوس کر پاؤں کہ غریب جنتا اس کنسرن سے کچھ روشنی دے سکے اور تھوڑے پیسے میں تھوڑے وقت میں کوئی ایسا ڈھانچہ کھڑا کر سکے جس میں اس کے ننھے ننھے بچے بچیاں پناہ لے سکتے ہیں مگر یہ اس لئے تھا کہ یہاں جو دہلی کی کریم آف سوسائٹی کہئے ریڑھ کی ہڈی کہئے ان کو شیلٹرز ملے مکان ملے -

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

مسٹر وائس چیرمین - میں یہ کہنا چاہونگا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مکانوں کی حالت اور بھی اکیوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے - پارلیمنٹ کے ممبران مکان حاصل کر نہ پائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر بڑے بڑے افیسر بھی مکان حاصل نہ کر پائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ مکان کی پرابلم آج بھی اسی طرح اکیوٹ ہے جیسے کہ اس وقت تھی جب اس کنسرن کو سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیا - یہ بات کہ ان کو آسانی نہیں تھی سیمنٹ کی اور لوہے کی • میں ایسا نہیں مانتا - آخر سرکار کے حق میں سرکار کے ہاتھ میں ایسی پاورس ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتی ہے تو اس کو آسانیاں ہو جاتی ہیں اس کو کچھ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی - اور اس کا فائدہ نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے - اس لئے اس کڑوے گھونٹ کو جو ان کنٹرولڈ سیکشن کی طرف مسٹر چورڈیا نے پلانی چاہی تھی اس کی طرف مسٹر اروڑا نے کوئی دھیان دینے کی بھی چنتا نہیں کی میرا کہنا یہ کہ آج اس بات کو طے کرنا ہے اس پارٹی کو جو پارٹی راج کرتی ہے اسے یہاں ایسے راستے کو اختیار کرنا ہے جس طرح کا ہمارے مسٹر بھوپیش گپتا جی کے ساتھی رشیا میں یا اور کمیونسٹ ممالک میں کر رہے ہیں تو پبلک سیکٹر میں یہ نہیں ہوگا جیسا ہے - یہ کنسرن جس کی آپ رپورٹ میں چرچا کرنے جا رہے ہیں یہ تو ایسی ہے جیسے جمنا میا میں باڑھ آ گئی ہے اور کچھ ننھے بچے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں - کوئی ستر پچھتر لاکھ یا ایک کروڑ سے دیش کا مسئلہ حل تھوڑا ہی ہونا ہے - میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک نمونہ ہے کہ کسی طرح سے ہم کسی کام کو

استثنی کرتے هیں - میں نہیں چاهتا
هوں کہلے صاحب کو اس کام کے لئے
بڑی مبارکباد دوں ویسے تو وہ بڑے
اچھے آدمی هیں بہادر هیں اور ویسے
میں کہہ دیتا هوں ارجن اروڑا کی
طرح کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کو اور ان کی
منسٹری کو بڑی مبارک باد لیکن وہ
جو انگلی اٹھا کر جمنا کی دھار کو
روکنے کی بات ہے وہ اس لئے کہ اس
کے ساتھ اور کبھی کروڑوں انگلیاں
اٹھیں اور اس کا ایک حل هو اور
جیسا کہ بھوپیش گپتا نے کہا یہ هی
کرنا ہے تو جگہ جگہ کرو کچھ لوگوں
کو بتاو راستہ دکھاو - یہ سٹر لاکھ
سے کام چلنے والا نہیں ہے - تو میں
نے جب اس کسوٹی سے دیکھا کہ آیا
یہ سرکار کی پالیسی ہے کہ اسی کو
آگے بڑھایا جائے تو میں نے دیکھا کہ
وہ بھی نہیں ہے -

کیونکہ [illegible] ری کا کام ٹھیک
نہیں چلتا تھا اس لئے سرکار نے اسے
اپنے هاتھ میں لے لیا - سرکار نے اپنے
هاتھ میں لے لیا اچھا کیا لیکن اس
سرکار کو کون اپنے هاتھ میں لیگا
جب چین کا ایگریشن هوا چین کا
حملہ هوا اس سے هماری سرکار جس
طرح نکمی ثابت هوئی بری طرح سے
نا کام رهی تو اس کی نالائقی کیلئے
هم نے سرکار کو الٹایا نہیں بلکہ اس
کو مضبوط کیا - اگر آپ دیکھتے هیں
کہ اس دیش میں پرائیویٹ سیکٹر

میں کہیں کمی ہے تو اسے دور کیا
جانا چاهئے جس طرح هم نے اور سب
اپوزیشن والوں نے یہ قسم کھائی ہے
کہ چین کے معاملہ میں شری مرار جی
ڈیسائی جتنا ٹیکس لگائینگے اتنا هم
دینے کے لئے تیار هونگے کیونکہ دیش
کو بچانا ہے هم یہ نہیں کہتے کہ
سرکار کو الٹا دینا چاهئے تو یہ دلیل
جیسے کہ شری بھوپیش گپتا نے دی
ہے کہ سب جگہ پر ڈالمیا بیٹھے هیں
ٹھیک معلوم نہیں دیتی ہے - وائس
چیرمین صاحب آپ اسی چیز کو
لے کر دیکھئے تو یہ حیرانی کی بات
ہے کہ سرکار جس چیز کو اپنے ادھیکار
میں کرنا چاهتی ہے اسے وہ کر لیتی
ہے میرے پاس ایسی بے شمار مثالیں
هیں جنہیں میں پیش کر سکتا
هوں - هم چاهتے هیں کہ دیش
میں نیشنلائزیشن هو اس لئے کہ
همارے پرائم منسٹر چاهتے هیں لیکن
اس وقت جو بحث ہے وہ ایسا
موضوع نہیں ہے اس لئے میں اس پر
نہیں جانا میں یہ کہنا چاهتا هوں
کہ اس ملک میں ایک ڈالمیا ٹاٹا
یا برلا هی نہیں ہے بلکہ سرکاری آدمی
اپنی جیب میں هزاروں برلا ٹاٹا اور
ڈالمیا رکھتے هیں - اگر ملک کی
توجہ اس طرح کی باتوں کی طرف
نہ جائیگی تو ملک کا بھلا کس طرح
هوگا ملک کی بھلائی اس میں ہے
وائس چیرمین صاحب - کہ سرکار

[شری عبدالغنی]

اس کمیشن کو ایسے رنگ میں ڈالے جیسے واقعی هاوسنگ پرابلم کا جو مسئلہ هے اس کے سالو کرنے میں یہ مددگار ثابت هو - اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جو چھوٹے چھوٹے دوکان دار هیں جن کی معمولی دوکانیں هیں وہ بھی بارہ پرسینٹ سے سینٹ پر سینٹ تک منافع کما سکتے هیں - همیں انکڑوں کی طرف نہیں دیکھنا چاهئیے همیں نتیجوں کی طرف دیکھنا چاهئیے کہ آیا مکان بنتے هیں کہ نہیں- سرکار خود اس طرح کے معاملوں میں آنکھ مچونی کا کھیل کرتی هے میرے ذاتی تجربہ میں آیا هے اور میں بتا دینا چاهتا هوں کہ سرکار نے یہ طے کیا کہ کتنے سینما چندی گڑھ میں بنیں گے - ٹھیک هے سرکار کو حق هے اس لئے اس نے ان جگہوں کا نیلام کیا کہ اس خیال سے کہ زیادہ پیسہ آئیگا - میں مانتا هوں کہ سرکار کے فنڈ میں زیادہ پیسہ آنا چاهئیے اور سرکار کو پیسے کی ضرورت هے لیکن کس جگہ پر جہاں سرکار کا انٹرسٹ تھا اور جہاں وہ پہلے اس جگہ کو نیلام کرنا چاهتی تھی چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اس کے لئے ٹینڈر مانگا گیا اس کو بھی چھوڑ دیا گیا پھر اس کے بعد اس جگہ کے لئے نیگوشیئشن کئے گئے اس لئے کہ جو سب سے بڑا مضبوط آدمی چیف منسٹر کا بیٹا تھا وہ خریدار تھا - اگر کوئی پبلک سیکٹر میں بلیک مارکیٹ کا کام کرتا یا کوئی ٹھیکیدار کرتا تو وہ تکلیف دہ نہیں هے لیکن اگر کسی اسٹیٹ کا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتا هے تو وہ زیادہ دکھ کی بات هے - اس وقت یہاں پر دو نقطوں پر بحث هوئی ایک تو یہ کہ جو نکمی کنسرن هے ان کو بھی سرکار اپنے هاتھ میں لے لے اور پبلک سیکٹر میں لے آئے - مجھے اس میں کوئی بحث نہیں هے کہ انہیں پبلک سیکٹر میں لایا جائے یا نہیں لایا جائے اور نہ میں ٹاٹا اور برلا و ڈالمیا کا مددگار هی هوں لیکن میرا کہنا یہ هے کہ پبلک سیکٹر کے نام پر نیشنلائزیشن کے نام پر آپ پانچ سو راجاوں کی جگہ پچاس هزار راجہ بناتے هو تو اس سے دیش کا بھلا هونے والا نہیں هے اور نہ هی دیش اس کو برداشت کرنے والا هے - اس لئے میں یہ کہنا چاهتا هوں کہ پبلک سیکٹر کے نام پر اس طرح کے راجہ بنائے جا رهے هیں اس کو بند کیا جانا چاهئیے پبلک سیکٹر کی کسوٹی یہ هے کہ لوگوں کا کہاں تک اس سے بھلا هوتا هے همارے مہر چند کھنہ صاحب مکان بنا کر دکھائیں جس میں غریب سے غریب جیتا رہ سکے -

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आपका टाइम हो गया ।

شری عبدالغنی : بھگوان چاہے گا تو میں ابھی بہت دیر تک زندہ رہونگا -

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : बोलने का टाइम हो गया है ।

شری عبدالغنی : تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر چلد کھنہ صاحب اس کنسرن میں اس طرح کا رنگ ڈالنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ اس کے ذریعہ دیش میں مکانات کافی تعداد میں بن سکیں اور لوگوں کو رہنے کے لئے سہولیت مل سکے - میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقعہ عنایت کیا -

†[**श्री अब्दुल ग़नी** : (पंजाब) : मैडम डिप्टी चेयरमैन ---मैंने बड़े ही ध्यान से आज की डिबेट को सुना । इस वक्त मेरे सामने पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की बहस नहीं है । आम तौर पर दोस्त कहते हैं कि तुम नेशनलाइजेशन के लिये क्यों कहते हो । मेरा कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर की सरकार जो है इसमें प्राइम मिनिस्टर का दिमाग इसी तरह वर्क करता है जिस तरह मिस्टर भूपेश गुप्ता का दिमाग वर्क करता है और आधी-आधी पालिसी किसी सरकार को कामयाब नहीं करती है और अगर सरकार फैल होती है तो देश फेल होता है । इसलिये मैं कहता हूं कि अगर कम्युनिज्म का ही रास्ता अख्तियार करना है तो पब्लिक सैक्टर को जितना चाहे बढायें लेकिन आज डालमिया का टाटा का सवाल नहीं । मैं देखता हूं कि बोगस फर्मों को परमिट नित नये दिए जाते हैं, लाइसस दिए जाते हैं, कोटे दिये जाते हैं । इनकी फैक्टरियां देखने में नहीं आती हैं लेकिन कर्जे दिए जाते हैं । खुदा करे ये बन्द हों । बोगस कैसेस के बारे में पार्लियामेंट में इधर या उधर ईवान में बहस हो वरना यह जो अर्जुन अरोड़ा भाई की शिकायत है कि जितने प्राइवेट कन्सर्न हैं, इनको जितना कण्ट्रोल का सामान चाहिये, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, वह अपनी जरूरत से ज्यादा लेते हैं और फालतू ब्लैक में चला जाता है

मिस्टर अरोड़ा खूब जानते हैं कि पब्लिक सैक्टर की जो कुछ बात हमारे सामने आई है वह इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है यहां तक कि एमरजेंसी के मौके पर गरीबों ने, अव्वाम ने दरमियाने तबके ने सिपाहियों के लिए काफी कुछ दिया और वह कलकत्ता के चोर बाज़ार में बिकता रहा किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं बेचा, किस प्राइवेट आदमी के हाथों में नहीं था इसलिए इस रिपोर्ट को जब देखता हूं तो मेरी कसौटी दूसरी है कि आया मैं भी इसी तरह चलूं जैसे आम हिन्दुस्तान का हिन्दू भाई जनरली और बाकी रहने वाला करता है ? कोई पूछता है कहिए बच्चे का क्या हाल है तो कहता है दुअन्नी भर आराम है । दुअन्नी चवन्नी और रुपये से बात करते हैं हिन्दुस्तान के लोग, इसलिए पहले मेरे भाई चौरड़िया जी आंकड़ों में पड़ गये इसके बाद मिस्टर अरोड़ा ने बारह परसेंट कह कर हमारे मिनिस्टर साहब को खुश करने की कोशिश की कि इनके ऊपर बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए । अगर मैं भी आंकड़ों में जाऊं तो मुझे भी अपने मिनिस्टर को मुबारिकबाद देने में खुशी हासिल हो सकती है लेकिन मैं रिपोर्ट को इस नुक्ते नज़र से देखता हूं कि क्या वह इस हिन्दुस्तान में जिस हिन्दुस्तान में करोड़ों इंसान हैं जिनको एक वक्त पेट भर खाना नहीं मिलता, जिस देश में करोड़ों ऐसे हैं जिनको सर छुपाने के लिए एक छोटी से छोटी झोंपड़ी मय्यसर नहीं है क्या इस कन्सर्न ने कोई ऐसा इन्क्लाब किया या इस इन्क्लाब की तरफ

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री अब्दल गनी]

कोई ऐसा कदम उठाया जिस से इन बेचारों को आसानी पैदा हुई हो, उनको सर छुपाने के लिए जगह मिल सकती हो अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो मुझे कोई ऐसा बात नज़र नहीं आती कि जिससे मैं यह महसूस कर पाऊं कि गरीब जनता इस कन्सर्न से कुछ रोशनी देख सके और थोड़े पैसे में थोड़े वक्त में कोई ऐसा ढांचा खड़ा कर सके जिसमें उसके नन्हें-नन्हें बच्चे बच्चियां पन्हा ले सकते हैं मगर यह इसलिए था कि यहां जो देहली की क्रीम आफ सोसाइटी कहिए, रोड़ की हड्डी कहिए उनको शैल्टर मिले, मकान मिले

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

मिस्टर वाइस चेयरमैन, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं तो यह समझता हूं कि मकानों की हालत और भी एक्यूट होती चली जा रही है । पार्लियामेंट के मेम्बर मकान हासिल करन पाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर बड़े-बड़े अफसर भी मकान हासिल न कर पाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन सच्चाई यह है कि मकान की प्राबलम आज भी उसी तरह एक्यूट है जैसे कि उस वक्त थी जबकि इस कन्सर्न को सरकार ने अपने हाथ में लिया । यह बात कि उनको आसानी नहीं थी, सीमेंट की और लोहे की, मैं ऐसा नहीं मानता आखिर सरकार के हक में सरकार के हाथ में ऐसी पावर्स है कि जब वह किसी चीज़ को करना चाहती है तो उसको आसानियां हो जाती हैं, उसको कुछ चीजें आसानी से मिल जाती है इसमें कोई मुश्किल नहीं होती । और इसका फायदा न हो यह भी नामुमकिन है इसलिये इस कड़वे घूंट को जो अन-कन्ट्रोल्ड सैक्शन की तरफ से मिस्टर चौरड़िया ने पिलानी चाही थी उसकी तरफ मिस्टर अरोड़ा ने कोई ध्यान देने की भी चिन्ता नहीं की । मेरा कहना यह है कि आज इस बात को तै करना है उस पार्टी को जो पार्टी राज्य करती है इसे यहां ऐसे रास्ते को अख्तियार करना है जिस तरह का हमारे मिस्टर भूपेश गुप्ता जी के साथी रशिया में या और कम्युनिस्ट मुमालिक में कर रहे हैं । तो पब्लिक सैक्टर में यह नहीं होगा जैसा यह है । यह कन्सर्न जिसकी आप रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं यह तो ऐसा है जैसे जमना मैया में बाढ़ आ गई है और कुछ नन्हें बच्चे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं । कोई सत्तर पचहत्तर लाख या एक करोड़ से देश का मसला हल थोड़ा ही होता है । मैं तो यह समझता था कि यह एक नमूना है कि किस तरह से हम किसी काम को स्टेडी करते हैं मैं नहीं चाहता हूं खन्ना साहब को इस काम के लिये बड़ी मुबारिकबाद दूं वैसे वह बड़े अच्छे आदमी हैं, बहादुर हैं, और वसे मैं कहे देता हूं अर्जुन अरोड़ा की तरह कि उनके डिपार्टमेंट को और उनकी मिनिस्ट्री को बड़ी मुबारिकबाद लेकिन वह जो अंगुली उठा कर जमना मैया की धार को रोकने की बात है वह इसलिए कि उसके साथ और कभी करोड़ों अंगलियां उठें और उसका एक हल हो और जसा कि भूपेश गुप्ता ने कहा यह ही करना है तो जगह-जगह करो कुछ लोगों को बताओ--रास्ता दिखाओ । यह सत्तर लाख से काम चलने वाला नहीं है । तो मैंने जब इस कसौटी से देखा कि आया यह सरकार की पालिसी है कि इसको आगे बढ़ाया जाये तो मैंने देखा कि वह भी नहीं है ।

क्योंकि इस फैक्टरी का काम ठीक नहीं चलता था इसलिए सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया । सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, अच्छा किया लेकिन इस सरकार को कौन अपने हाथ में लेगा जब चीन का एग्रेशन हुआ, चीन का हमला हुआ उस समय हमारी सरकार जिस तरह निकम्मी साबित हुई और बुरी तरह से नाकाम रही तो इसकी नालायकी के लिए हमने सरकार को उलटाया नहीं बल्कि इसको मज़बूत किया । अगर आप देखते हैं कि इस देश में प्राइवेट सैक्टर में कहीं कमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिये जिस तरह हमने और सब अपोजीशन वालों ने यह कसम खाई है कि चीन के मामले में श्री मोरारजी

देसाई जितना टैक्स लगायेंगे उतना हम देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि देश को बचाना है। हम यह नहीं कहते कि सरकार को उलट देना चाहिए तो यह दलील जैसे कि श्री भूपेश गुप्ता ने दी है कि सब जगह पर डालमिया बैठे हैं ठीक मालूम नहीं देती है। वाइस चेयरमैन साहब, आप उस चीज़ को लेकर देखिए तो यह हैरानी की बात है कि सरकार जिस चीज़ को अपने अधिकार में करना चाहती है उसे वह कर लेती है, मेरे पास ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिन्हें मैं पेश कर सकता हू। हम चाहते हैं कि देश में नेशनलाइजेशन हो इस लिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं लेकिन इस वक्त जो बहस है वह ऐसा मौजूं नहीं है इसलिए मैं इस पर नहीं जाता मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में एक डालमिया, टाटा या विड़ला ही नहीं है बल्कि सरकारी आदमी अपनी जेब में हजारों बिड़ला, टाटा और डालमिया रखते हैं। अगर मुल्क की तवज्जी इस तरह की बातों की तरफ न जायेगी तो मुल्क का भला किस तरह होगा, मुल्क की भलाई इसमें है वाइस चेयरमन साहब कि सरकार इस कन्सर्न को ऐसे रंग में डाले जैसे वाकै हाउसिंग प्रोब्लम का जो मसला है उसके साल्व करने में यह मददगार साबित हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी मामूली दुकानें हैं वह भी बारह परसेंट से सेंट परसेंट तक मुनाफा कमा सकते हैं। हमें आंकड़ों की तरफ नहीं देखना चाहिये, हमें नतीजों की तरफ देखना चाहिये कि आया मकान बनते है कि नहीं। सरकार खुद इस तरह के मामलों में आंख मिचोली का खेल करती है। मेरे ज़ाती तजुर्बे में आया है और मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने यह तय किया है कि कितने सिनेमा चण्डीगढ़ में बनेंगे। ठीक है सरकार को हक है कि इसलिए इसने इन जगहों का नीलाम किया कि इस ख्याल से कि ज्यादा पैसा आयेगा। मैं मानता हूं कि सरकार के फण्ड मे ज्यादा पैसा आना चाहिए और सरकार को पैसे की जरूरत है लेकिन किसी जगह पर जहां सरकार का इंटरेस्ट था और जहां वह पहले इस जगह को नीलाम करना चाहती थी, छोड़ दिया गया इसके बाद इसके लिए टेंडर मांगा गया उसको भी छोड़ दिया गया फिर इसके बाद उस जगह के लिए नेगोशिएशन किए गये इसलिए कल जो सबसे बड़ा मज़बूत आदमी चीफ मिनिस्टर का बेटा था वह खरीदार था। अगर कोई पब्लिक सैक्टर मैन ब्लेक मार्केट का काम करता या कोई ठेकेदार करता तो वह तकलीफदेह नहीं है लेकिन अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता है तो वह ज्यादा दुख की बात है। इस वक्त यहां पर दो नुकतों पर बहस हुई एक तो यह कि जो निकम्मी कन्सर्न है उनको भी सरकार अपने हाथ में ले ले और पब्लिक सेक्टर में ले आये। मुझे इसमें कोई बहस नहीं है कि इन्हें पब्लिक सेक्टर में लाया जाय या नहीं लाया जाये और न मैं टाटा और बिड़ला व डालमिया का मददगार ही हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि पब्लिक सेक्टर के नाम पर नेशदलाइजेशन के नाम पर, आप पांच सौ राजाओं की जगह पचास हजार राजा बनाते हों तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है और न ही देश इसको बरदाश्त करने वाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के नाम पर इस तरह के राजा बनाए जा रहे हैं इसको बन्द किया जाना चाहिये। पब्लिक सेक्टर की कसौटी यह है कि लोगों का कहां तक इससे भला होता है हमारे मेहर चन्द खन्ना साहब मकान बना कर दिखाएं, जिसमें गरीब से गरीब जनता रह सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : आपका टाइम हो गया।

श्री अब्दुल ग़नी : भगवान् चाहेगा तो मैं अभी बहुत देर तक जिन्दा रहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : बोलने का टाइम हो गया।

श्री अब्दुल गनी : तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेहर चन्द खन्ना साहब इस कंसर्न में इस तरह का रंग डालने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से इसके जरिए देश में मकानात काफी तादाद में बन सकें और लोगों को रहने के लिए सहूलियत मिल सके । मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका अनायत किया ।]

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Sir, I rise to congratulate the Minister of Housing for the excellent work that has been done under the auspices of his Ministry in the public sector. It is not my intention to speak extensively on this simple Report on this undertaking which, in its own way, has achieved some good results. I was just thinking of the possibilities of extending the activities of this undertaking on a country-wide scale. I was certainly happy that our good friend, Shri Bhupesh Gupta, was referring to the need for companies of this kind all over the country, undertaking projects in the villages, small towns and cities. It was reported in the papers that Russia in this respect has achieved a great success, that every few minutes or so, they are able to construct a house and make it worth living. The need for this kind of undertaking is very great in our country where housing shortage is very acute not only in the cities and towns; but the condition in the villages is very awful. I do not know why the Central Government or Mr. Khanna did not venture to advise all the States to undertake work of this kind which ought to have been done. This factory has done a good job in these nine or ten years of its existence and year after year more profits are being shown. Even as a business proposition, it is a good success, I should think.

I want to invite your attention and the attention of this hon. House to another aspect of this question. What is happening in the countryside? Of course, everywhere—right from Kanyakumari to the Himalayas —this is the aspect. In any kind of construction of a house, the most important portion is wood. Next comes brick or whatever that is needed. In the countryside the devastation of the trees has been occurring at such an enormous rate that the future looks very gloomy and bleak indeed for me. Wherever I travel—I have travelled through a number of States—everywhere I find that the felling of trees has been going on at a colossal rate, far greater than the growth output of trees, with the result that apart from the fact that the soil is getting depleted of nutrition, the scarcity of wood is enormously felt at every place, in almost every village.

SHRI BHUPESH GUPTA: Some years ago the *Vanamohotsava* was started. What has happened to it?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: The *vanamahotsava* is there. Before the timber could be made use of, the trees have to grow for at least one hundered years, I am told.

We find that for the last hundred years or so we have been cutting the trees at an enormous rate, and depletion has been taking place, and I am sure before long this spectacle of our country would be a very sad affair indeed. This is what I see. Therefore what is the alternative? Under the impact of increasing population and increasing cattle, goats, sheep, etc. felling of tree has become very necessary and the foliage thereof is being used for feeding the cattle, so much so trees are not growing in the countryside. Therefore the only alternative is that cement and iron must take the place of wood in this country for housing purposes. There is no other alternative. If we do not do it I do not know what will happen. I shall not go to the extent of saying

that the countryside would be converted into desert. After all, in the course of human civilisation, on account of reasons of this kind, due to destruction of vezetation many deserts have sprung up and organic matter has not been allowed to grow. Therefore, Sir, I would like Mr. Khanna, a bold and intelligent person as he is, to take courage in both the hands and spread the philosophy of cement and iron and concrete in place of wood wherever wood can be done away with for construction purposes. Now even for burning bricks there is no wood in the countryside. Why for burning bricks, even for cooking food there is not enough of wood in the countryside. This is a very very serious situation, Sir. I had no intention of speaking, I rose only to bring to the kind notice of the Minister, Mr. Khanna . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: But do you know how they wanted to solve this problem? They advised their Governors to plant trees in their Raj Bhavans and I know Miss Padmaja Naidu was doing it in Bengal.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Now allow me to have my say in the matter. I know for example that, in my State of Mysore, to all the Harijans and Scheduled Castes they started giving wooden door frames and wooden panels, I mean, for shutters, for windows, doors, etc., but before long, within five or six years, the white ants have got away with all the wood, with the result that the entire housing scheme in Mysore State was declared a failure. Now, if instead of giving wood, if instead of cutting the natural wealth of the country, destroying it, and giving it away as food for white ants, instead of doing it, if concrete frames for doors and windows and concrete beams and rafters, etc., had been provided, on the one hand they would have lasted for long; the houses would have been saved from destruction of the wooden structures by white ants; on the other, vegetation growth could have been preserved for the well-being of the country.

Therefore, Sir, I would suggest to our hon. Minister to take up this question and come before the House next year and tell us that he had taken up the matter with the State Governments with success. I am not very much scared of the private undertakings, if they can do the job well. Of course Mr. Bhupesh Gupta might not agree, but whatever it is, let everybody construct houses with these materials. But then it requires more cement and more iron which are scarce materials nowadays, and of course in time to come I am sure the country will be able to produce enough of cement and enough of iron, and therefore the entire housing scheme could be helped with the increase of cement and iron. But before long he can make available his experience with the present undertaking. At least in every State let there be a counterpart of this undertaking to start with, and for the time being let it be a public sector undertaking. I do not mind what sector it is so long as they are made available. The need for housing is very very great. Next to food shelter is the most important thing and that is the *sine qua non* of civilisation also, the progress that we are making in giving more amenities to human beings. Therefore, Sir, I request the hon. Minister to take courage and spread it out in every State and every city and every district.

Thank you very much.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I had no intention to take part in this debate, but as I listened to the speech of my esteemed friend, Mr. Bhupesh Gupta, I was reminded of the visit that we paid to certain places in Moscow. Both I and Mr. Akbar Ali Khan had the pleasure of going round the city, the city that was going up, the new housing schemes, and I wanted to see something on those lines to be done in our country also.

[Shri P. N. Sapru.]

Much has been said about the public and the private sectors. Well, the House knows that my sympathies are generally with the public sector, and I am glad that this public undertaking—though it is a company under the Indian Companies Act, it is a Government-owned company—this public concern has done rather well, and the Minister deserves to be congratulated on the efficiency with which this concern has been run.

Housing, I think, is one of the most important problems that a welfare society should provide. This is the name given to a welfare State by Lord Beveridge—he called it welfare society. Now I am reminded of some of the experiences which I had in 1944 or 1945 when I was working as Chairman of the Industrial Health Committee and when, in that capacity, I had to visit some of the industrial centres of India, and I cannot forget the ugly scenes which I saw in the town of Kanpur, where the houses were full of dirt and squalor, and like scenes in some of the slum areas of Calcutta and Bombay, and we wondered whether human beings could live in those surroundings.

Well, I think the rents which are charged in Delhi for the lower middle class people or the poor middle class people are exorbitant. Even higher middle class people have to pay exorbitant rents in this city. I am told that you cannot get a good flat here for less than Rs. 800 a month, and Rs. 800 is the salary of a District and Sessions Judge in our State, and this is the sort of thing that is happening in big cities like Delhi and Calcutta and Bombay. I think it is essential therefore that we should pay some attention to this question of housing. Next perhaps to food, housing is the most important requirement of man. I would say that housing is an important requirement even from the point of view of health. Without good housing you cannot have a healthy nation, and without having a healthy nation you cannot be a nation which can defend itself. Even from the point of view of defence, expenditure on housing is expenditure on the defence of the country. Even if it is from the point of view of defence, expenditure on housing is justified, would be justified even in war-time. Housing cannot be left entirely to private enterprise. We are getting sick of the running down of the public sector by the private sector, in season and out of season, by persons who are interested in the maintenance of certain vested interests. We have taken in this matter a view which is consistent with public welfare, and public welfare requires that the State should take an increasing interest in having houses provided for the poorer sections of the population.

I think that without State aid it will not be possible for us to solve the problem of housing. This is a small concern which has got a paid-up capital of about Rs. 40 lakhs but it has got a reasonable dividend and I think this dividend will go up. It is also necessary from the point of view of the Indian tax-payer that we should undertake some public undertakings or rather we should run some public undertakings in order that we might have increased revenues for our growing expenditure. It is not desirable that we should go on multiplying this indirect taxation from every point of view. I think this question of prefabricated houses deserves attention and consideration of the House. I am glad that my young friend, Mr. Vimalkumar Chordia, has drawn our attention to this report and that hereafter, in future, we shall discuss the report as closely as we discuss certain other reports.

I would also like to say that as a matter of principle I would like the State to have dealings with the State Bank of India. I am not reflecting on any particular bank. I am not saying that the Punjab National Bank is not good or is not well-managed. It will be wrong for any one to make a statement of that character about a

bank which has some reputation in the country. But, I think, as a matter of principle it is desirable that the State should have relations with its own bank which is the State Bank of India. There, I think, I am in agreement as a matter of principle with Mr. Bhupesh Gupta.

Sir, prefabricated houses, I think, should be built. We have here some account of the work which has been done by the Delhi Administration in regard to these prefabricated houses. They are doing the three-storeyed house building in Ramakrishnapuram, and they have been given the contract for the construction of a building for the Delhi Polytechnic. About this concern all that I can say is that it is doing good work and it deserves encouragement from this House.

I would like, before I conclude, to thank the Minister for the ability and efficiency with which his Directorate, which is answerable to him, has been running this concern. I should have liked on this directorate, however, some representative of the lower middle classes or the working classes to be appointed.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is right.

SHRI P. N. SAPRU: In selecting our directorates we have only civil servants. I would rather like our directorates to be chosen from a wider circle. I do not think that monopoly or wisdom in managing concerns rests with those who are more fortunately born in life.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: Mr. Vice-Chairman, Sir, my task has been made much easier by the previous speeches. In a way I am also grateful to Mr. Chordia for having brought forward this motion before the House. Sir, very valuable suggestions have been made both in regard to the housing policy of the Government of India and also in regard to prefabricated housing in the context of this Hindustan Housing Factory. Sir, I would like to say a few words about the housing policy of the Government of India because many Members have touched upon it.

Sir, we undertake housing in two particular ways. One is social housing that we undertake through the State Governments and the other is contract housing which is undertaken by the Ministry of Housing through the Central Public Works Department. As far as social housing is concerned, I fully agree with Shri Sapru that housing occupies a very important place in our society. Food, clothing and shelter, we have always been proclaiming that they are the three tenets of our socialistic pattern of society. And I do admit that as far social housing is concerned—and in social housing I include low income group, middle income group, rental housing, industrial housing, so on and so forth—it has not received the same attention as it should have received in our Plans. I am not blaming the planners. After all, they have to take the finances of a country into consideration. They have also to take the State resources into consideration. But, Sir, it is a fact that while the population of the country has been growing and growing very fast, during the last ten years, 1951-1961, there was a rise of over 21 per cent., but in that period the allocation under housing was brought down from 34 per cent. to 15 per cent. under the Third Plan. That has been our misfortune. And, Sir, the States too, in spite of the fact that the allocations have been lowered, have also not been very active or enthusiastic about the housing programmes. There have been surrenders. There have been lapses and some of the houses which were built for the industrial workers have been allotted to non-entitled persons, and when the emergency started even the allocations made for housing in the State plans have been diverted to other projects. They are good projects, important projects, but if we concede and accede that housing gives a man certain amount of satisfaction, secu

[Shri Mehr Chand Khanna.]

rity, a life, a home, housing has to receive some priority, if not a very high priority.

Sir, I have taken this up very recently with the Finance Minister as well as with the Planning Minister. I have also been to the Life Insurance Corporation. The Life Insurance Corporation has been very helpful. They gave us an allocation of Rs. 60 crores under the Third Plan. They are not in a position to raise this allocation. But as far as the Planning Commission. is concerned, they have assured me that they are going to give industrial housing a very high priority a productive scheme because unless we have houses for the workers, I feel, Sir, we shall not be able to step up our industrial programme.

Now, Sir, I come for a short while to the housing which is undertaken directly by my Ministry. A reference has been made to Delhi. A reference has been made to the unfortunate conditions under which Government servants have to live, and the last speaker very rightly remarked that the rents in Delhi are on a very high side. I have to accept all those premises Since I took charge of this Ministry it is nearly a year now. I fully examined the problem from all its aspects. I found, Sir, that previously we have been more concerned with paying house rent allowances to our government servants. We have been taking property on leases. We have been requisitioning properties, sometimes paying very heavy rents and at the same time maintaining those properties which belonged to other people. If all these years all the money that has been paid as rent or as house rent allowances, if that money had been diverted to the construction of houses, I am sure that the housing difficulties in Delhi and other parts of the country like Madras, Bombay and Calcutta would not have been so acute. It is a fact that the Government servant who has a house has a different outlook. He works in a different way but nearly 66 per cent of the Government servants in Delhi have to take houses on high rents, have to pay very heavy rents and sometimes they have to live very far away from Delhi. During this year we have sanctioned housing schemes to the tune of Rs. 15 crores. In the last 5 years of this Ministry, schemes were sanctioned only to the extent of Rs. 7½ crores. I am not casting any aspersions. What I am trying to say is this that I have doubled the programme of housing within one year as compared to what was done during the last 5 years. I hope that we should be able, within the next few years, to give a certain amount of satisfaction to the Government servants . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: You double your efforts.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: . . . . who have to work under very difficult conditions in Delhi. It is not a very happy position in which I am when I am told by the Government servants who come to see me that every Minister has a house—I cannot deny that —every Member of Parliament, more or less, has been provided with some sort of accommodation, Members of the Planning Commission, Judges of the Supreme Court, senior officers, every one of them has a house and possibly very near to the place of work but as far as the poor Government servants are concerned who come under Classes III and IV, most of them have no accommodation and many of them have to live at very long distances. I am looking into that aspect of the matter and with the support that I have got from the House today and the encouragement that has been given to me, I only hope and pray that I am worthy of the confidence that you have reposed in me.

I come to the Hindustan Housing Factory. As regards the Hindustan Housing Factory, it has had a very chequered career. Perhaps most people do not know how it came into being. After partition, when there was

a mass exodus of human population and in Delhi you found people lying on the streets in Chandni Chowk, in Cannought Circus all over, and the building material seemed very scarce —I mean it was soon after partition —then we had to go and find out how best we could provide houses. We undertook additional construction and then we came across this foam-concrete process which I believe was more or less in an experimental stage then. We had an officer working with us then, Dr. Otto Koenisberger and I would like to pay him a tribute today. He was the man who foresaw this and he was the man who helped us in setting up this factory but it had a very bad start. We were faced with difficult times. It is no denying the fact that for the first 5 or 6 years we had to face very rough weather but as it has been remarked, since 1955 we have turned the corner. Every year there has been a steady progress and while profits have been there—Sir, I am not very keen about the profit motive, there should be profits, I do admit and perhaps in the public sector undertakings there should be no losses because the criticism is always acute, as Mr. Sapru remarked, from the vested quarters but—the main idea today is to provide a house, a shelter to our countrymen to a poor man, whether he lives in an urban area or whether he lives in a rural area and if I can give him a good comfortable house at a cheap rate, I should be happy. The idea is to give him shelter. The idea is to give him a home. The idea is not to make money out of his vicissitudes. That is not my idea at all. So I am glad that we have not made any losses but the production has been steadily rising. It was about 30 lakhs in 1955. It expanded and went up to 40 lakhs or 50 lakhs and according to the report, as you may have noticed, it was 70 lakhs in 1961-62. In the year 1962-63, our production has gone up to 90 lakhs and during this year, in 1963-64, we are hoping to reach a target of 140 lakhs. That is the peak. Beyond that we cannot go. I wish to tell Mr. Gupta and others that we have expanded the factory. We have done so during the last few months. We are running double-shift. We have got about 1600 workers who are working night in and day out and the factory which had a very small production is now having a very big production and, as I said earlier, it is not also running at a loss. I am not very much concerned with the profit. If any tribute is to be paid, the tribute is to be paid to the workers and the management. I do not deserve any congratulation. I do not deserve any credit or any recommendation. There are 1600 workers in this factory and since the emergency started, when I needed production, they have worked and given me wilful co-operation. There is no trouble or dispute pending between them and the management. May I take the House into confidence and say that 3 or 4 months ago I was so fortunate, I was so happy because I was invited by these very workers who at one time threatened a strike and they presented me with a purse of Rs. 15,000 for the National Defence Fund? It is not a small sum of money. A big man who rolls in wealth can give lakhs. (*Interruptions*) I have said so before and I do not mind repeating it before the House. Possibly he gives to the N.D.F. in the form of a cheque to the Prime Minister of India and claims Income-tax exemption from the Finance Minister on the other side.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is right.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: I do not want to say all that but I do say about a worker who works at Re. 1 or Rs. 2 a day or Rs. 3 a day that if he gives me his Sunday or Saturday's wages and if he gives me Rs. 15,000 towards the N.D.F., I say that he is the man who deserves the credit and not me or the Ministry. Let me say about them, as I have said so, there is no dispute pending. That was the last report—it was for 1961-62—and in 1962-63 those differences have been resolved.

[Shri Mehr Chand Khanna.]

It has been stated and very rightly that we should expand these factories. I fully endorse that view and I entirely agree with all my hon. colleagues here. In the last 6 months we have been making very great efforts. We have been in touch with the U.S.S.R. We have been in touch with Czechoslovakia and we have been in touch with Poland and my idea is not to have another factory in Delhi only but also to have a factory, one in Madras, one in Bombay, one in Calcutta and another factory in Delhi. The machinery that we will import will come to roughly Rs. 70 lakhs each. For that I need foreign exchange.

SHRI AKBAR ALI KHAN: In any one of the Southern States, why Madras?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: I should say the Eastern region, the Western region and the Northern region—I should put it more correctly. I need not go to Madras. I can go to Hyderabad for the matter of that. That was not my intention at all

SHRI BHUPESH GUPTA: You can get money also there.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Is it very difficult to provide one for each city?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: Let me tell you that I am one with you. The only point is that you must have the raw materials round about it. Then on the top of it. generally up till now I have been thinking in terms of my own requirements as the Government. I have Government servants in Madras, in Bengal, in Bombay and all those places where I could not provide them with accommodation. My first anxiety as the Housing Minister or Works Minister has been, as they say 'Charity begins at home' and I have been thinking in terms of all those places. I do not want to take much of the time of the House, I would only say that by all that has been stated in this House today I feel emboldened and I feel strengthened in my ideas and I feel that with the blessing of this House and with the support that the House is giving I propose to bring this matter to the notice of the Prime Minister and I shall tell him: "Sir, this housing factory has proved a success". Today we have placed orders with this factory to the extent of Rs. 150 lakhs. Orders for Rs. 85 lakhs we ourselves have placed from the Ministry, works which used to be done by the Central P.W.D., we have given them all that order. We are now putting up a big construction programme covering seven lakh square feet, in Ramakrishnapuram and the cost of that is going to be Rs. 70 lakhs. Then we are building in another place in the precincts of Patiala House where our Health Ministry has shifted, and so on and so forth we have given them orders to the extent of Rs. 150 lakhs. The factory cannot take any more orders. I wish I could give them more orders, because for one thing I find that the cost of construction is cheaper. That is number one Then the time factor is much less. And thirdly I hope my own department of which I happen to be the Minister I will be able to take it out from the rut of traditional housing and bring it to prefabricated housing. Up to now the general feeling in the P.W.D. is that we must stick to our own old traditional housing. Today it so happened that my Chief Town Planner, Mr. Joglaker, arrived back from Russia. He was there on a short tour and we were out this morning towards Janpath and I asked him, "What about prefabricated housing in Russia?" and he said, "Doing remarkably well". And then I said, "Go and tell the Chief Engineer and the Central P.WD. on my behalf that if Russia, an advanced country, can make such rapid progress in housing, we can do the same thing in Delhi". The C.P.W.D. is a good department. I have nothing to say against it. They have done good work before and they are doing much better now, and they are capable of delivering the goods. Taking ill of this

department or that will lead us neither here nor there. Mr. Ghani talked of many things, about moral values of corruption and so on. After all they are relative terms and I do not want to get involved in these things and I do not want to bring in Punjab politics into the Hindustan Housing Factory.

شری عبدالغنی : یہ پنجاب کی پالیٹیکس کی بات نہیں ہے یہ سب جگہ کے فنڈس کی بات ہے یہ مفید چیز ہے اور اس کا مس یوز نہیں کیا جانا چاہئے -

†[श्री अब्दुल गनी : यह पंजाब की पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यह सब जगह के फण्ड्स की बात है । यह मुफीद चीज है और इसका मिसयूज़ नही किया जाना चाहिये ।]

श्री मेहरचन्द खन्ना : अभी जनाब ने फरमाया था कि सिनेमा के लिए जगह बिकी और उस सिनेमा में किसी बड़े के बेटे का हाथ था ।

شری عبدالغنی : چیف منسٹر کے بیٹے تھے -

†[श्री अब्दुल गनी : चीफ मिनिस्टर के बेटे थे ।]

श्री मेहरचन्द खन्ना : दिल्ली में तो चीफ मिनिस्टर नही हैं, दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर हैं, और हम सब उनके बेटे हैं । उन का कोई बेटा नहीं है इसलिए प्राइम मिनिस्टर की बात नही होगी । चीफ मिनिस्टर साहब से आपका ज्यादा प्यार है, इसलिए मेरा खयाल है यह पंजाब की बात होगी । चूंकि आप मेरे पुराने दोस्त हैं ।

I was talking about the Housing Factory and I do not want to say much beyond this. There are just one or two points that have been made and I shall briefly touch on them.

Mr. Bhupesh Gupta referred to the General Manager. I do not know much about it. We have a Superintending Engineer, a very capable officer. He was in Bombay and I asked him specially to come and I am glad to say that since he has come here our capacity has practically been doubled. There was no trouble between the management and labour and he has done remarkably well. I wish I could give him a little more, but it is not within my power. There is no question of paying him less.

Another thing is about the woodwork department. I am glad Mr. Chordia has touched upon something which was my weak spot and as Mr. Arora very rightly pointed out, all the good things that the factory has done he completely ignored. Anyhow, I do not blame him for that. He is a young man, with plenty to learn and the time will come when even wisdom and good sense will prevail. But I may tell him that this particular department had difficulties, particularly in the purchase of wood. It has to be purchased in auctions at Kashmir, Naini Tal, etc. The wastage in wood is now utilised to the extent of 80 per cent and we have started manufacturing flush doors for private parties from timber supplied by the customers. We hope there will be no losses from this department now. Seasoning kilns are now running to full capacity.

†[ ] Hindi transliteration.

[Shri Mehr Chand Khanna.]

Then there was a reference to the Punjab National Bank. Here, Sir, I am on a weak wicket. In good old days when I belonged to a certain sector, not the present sector—I am talking of the time before partition—I was myself a director of the Punjab National Bank. It was a good bank and it was in good hands. If it has changed after partition, it is no concern of mine. It may be good, bad or indifferent. But the position is that we are using the Punjab National Bank as a bank with a view to depositing our daily cash and cheques. Otherwise whatever flows beyond Rs. 10,000 goes to the State Bank. But that being the nearest to us, we make use of it. I wish to say that I have nothing against the Punjab National Bank, just because that bank has as chairman somebody who is allergic to Mr. Bhupesh Gupta and Mr. Bhupesh Gupta is allergic to him and I am not going to contaminate the . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: But you have appointed an enquiry into his affairs. You have ordered an enquiry into his affairs.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: If during these six or seven years Mr. Gupta and myself have agreed with each other, it is on this Hindustan Housing Factory and I feel so happy and fortunate today that even Mr. Gupta feels that myself and my Ministry are capable of doing good things. Thank you, Sir, and it will be my endeavour to see that this factory goes on working even better and we will try to set up a number of factories not only in Delhi but in other parts of India so that our housing programme can be strengthened and its tempo can be increased and even the poor people living in the rural areas may take advantage of these prestressed housing materials. That will be my endeavour and my privilege. Thank you, Sir.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, विशेष कुछ कहने को नहीं रहा, मगर कुछ बातें जो माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा में की उन पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। हमारे माननीय सदस्य श्री अरोड़ा जी का वक्तव्य सुन कर तो ऐसा लगा जैसा किसी पीलिया के मरीज को सब पीला ही पीला दिखलाई देता है। वैसी ही आपकी भावना राष्ट्रीयकरण के बारे में बन गई है कि जिस चीज का राष्ट्रीयकरण हो जाता है वह अच्छी बन जाती है, जिस जिस के ऊपर राष्ट्रीयकरण का लेबल लग जाता है वह सब अच्छी हो जाती है और जितने भी पाप हैं वे सब अच्छे हो जाते हैं। मेरे नम्र मत में किसी चीज पर रष्ट्रीयकरण का लेबल लग जाने से वह चीज अच्छी नहीं हो जाती है और न खराब ही होती है। जैसा कि मैंने अभी पीलिया का उदाहरण दिया कि पीलिया के मरीज को सब जगह पीला ही पीला दिखाई देता है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयकरण का भूत हमारे माननीय सदस्य के दिमाग में चढ़ गया है। केवल राष्ट्रीयकरण ही ऐसी औषधि है ऐसी रामबाण औषधि है जिसके द्वारा सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में मतभेद है।

श्री अर्जुन अरोड़ा: इस औषधि को खाकर देखिये।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: मेरा निवेदन यह है कि कोई काम राष्ट्रीयकरण के द्वारा अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। चूंकि मैंने इस डिपार्टमेंट की कुछ खराब बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो माननीय मंत्री जी भी कहने लगे कि "गुड सेन्स विल प्रिवेल" करेगा। मैं चाहता हूं कि अगर उनके दिमाग में "गुड सेन्स प्रिवेल" करे तो वे वुड डिपार्टमेंट में जो घाटा है और जिसमें एक

पैसे का भी लाभ नहीं दिखलाया है, इस तरह की बात कब तक चलती रहेगी ? उन्होंने अपने जवाब में कहा कि सीजनल प्लान्ट पूरी तरह से काम कर रहा है काम ठीक चल रहा है लेकिन वुड डिपार्टमेंट में घाटा है। इसके बारे में आपकी रिपोर्ट कहती है कि १-८-५६ से ३१-८-५७ तक १५·६४ लाख रुपये का प्रोडक्शन आपके वुड डिपार्टमेंट में हुआ। और १-४-६१ से ३१-३-६२ तक ४·४१ लाख रुपये का प्रोडक्शन हुआ। आपके वुड डिपार्टमेंट में आपके कथनानुसार पूरी तरह से काम हुआ फिर भी उसमें घाटा हुआ। मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य महोदय के दिमाग में यह बात समा गई है कि सब बुराइयों की रामबाण औषधि "राष्ट्रीयकरण" ही है। यह बात नहीं है। हर चीज के मर्ज़ को दूर करने के लिए अलग अलग औषधि का प्रयोग करना पड़ता है। यह बात ठीक है कि १२ प्रतिशत का नफा हुआ है लेकिन अगर पूंजी के आधार पर देखा जाये तो उससे भी ज्यादा नफा मालूम पड़ेगा। माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट में जितनी भी तारीफ की बातें थीं उनके बारे में कह दिया। क्या तारीफ के पुल बांधने के लिये यहां पर प्रस्ताव रखा गया है ? मेरा मकसद तो इस संस्था में जितनी खराबियां है उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। इस संस्था में जो कुछ कमियां हैं उनको दूर कराने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मैंने यह प्रस्ताव इसलिये नहीं रखा कि इस सदन में यह बात कहूं कि इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। वास्तविकता यह है इस संस्था में जो बुराइयां हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना अत्यन्त आवश्यक है। प्रशंसा तो रिपोर्ट में की ही गई है।

5 P.M.

ब्लैकमार्केटिंग की बात हमारे माननीय अरोड़ा साहब ने कही, यह तो उनके और हमारे दोनों के शासन की क्या हालत है, इसको प्रगट करता है। और प्राइवेट सेक्टर ब्लैक करता है या पब्लिक सेक्टर नहीं करता है इसकी मेरिट और डिमेरिट पर मैं नहीं जाता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो प्राफिट वह अर्न करता है उसके मुकाबिले में हम कहां तक स्टैंड करते हैं। इस के अलावा हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम यह देखें कि जितने ऐडवांटेजेज़ गवर्नमेंट को हैं, क्या उतने ही ऐडवांटेजेज उनको भी है ? हम तो चाहते है कि दोनों पर चल करके अपनी क्षमता बताये, अपना लाभ बताये, या अगर अपना लाभ न बतायें तो यह बतायें कि पब्लिक को या कंज्युमर को कितना लाभ होता है, कितनी सस्ती अच्छी सामग्री उसको मिलती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इन बातों में एकतरफा लक्ष्य करके चलने से कोई काम नहीं होता। मैं न तो प्राइवेट सेक्टर का हामी हूं और न पब्लिक सेक्टर का दुश्मन। मैं तो दोनों की मैरिट को तौल करके देखना चाहता हूं कि हमारे देश के लिये कौन लाभदायक है। मैं अपने देश का हामी हूं और देश के लिये जो लाभदायक है, उसी का मैं हामी रहूंगा चाहे आप अपने प्रिजुडिस्ड माइंड से कुछ भी कहने का प्रयास करें, उससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने सामने एक दृष्टिकोण रख करके चलें कि राष्ट्र का किस में हित है और उसी हित को सामने रख करके काम करें, तभी देश का भला होगा। केवल किसी नारे में बह जाना और केवल समाजवाद के नारे में बह करके अपनी समझ को भी भुला देना, कुछ न्यायसंगत नही प्रतीत होता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 23rd April 1963.

GMGIPND—RS—101RS—7-6-63—550